भाजपा कार्यकर्ता बिना स्वार्थ के राष्ट्र सेवा के लिए काम करता है- भजनलाल

पार्टी किसी एक व्यक्ति या परिवार की नहीं, पुराने अनुभव के साथ नया जोश जरूरी है- बी.एल. संतोष



जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित हुई भाजपा की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।

■ **भाजपा की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि संगठनात्मक कार्यशाला का उद्देश्य राजनीति करना नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को मूल्यों, आदर्शों व जन सेवा से जोड़ना है।**

जयपुर, 3 जनवरी । भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जयपुर में आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन सत्र को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तथा भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने संबोधित किया। इस दौरान भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, भाजपा की राष्ट्रीय सचिव डॉ. अलका गुर्जर, राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पुनिया तथा अशोक परनामी सहित, पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए बीएल संतोष ने कहा कि पार्टी किसी एक व्यक्ति और परिवार की नहीं है। नए लोगों को भी सम्मान मिलना चाहिए। नए लोगों के आने से पार्टी में नयापन आता है। उन्होंने कहा कि पुराने लोगों को नए लोगों को स्वीकार करना चाहिए। पुराने अनुभव के साथ नया जोश भी जरूरी है। आपस में मिलकर समन्वय बैठाते हुए किस तरह से काम किया जाए, यह जरूरी है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी ताकत हमारे कार्यकर्ता हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के राष्ट्र सेवा के लिए काम करते हैं।

भाजपा कार्यकर्ताओं की यह कार्यशाला भाजपा के संगठन को प्रदेश, जिला, मंडल और बूथ तक सक्रियता से मजबूत करने के साथ ही, केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेगी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रिकार्ड बनाते हुए 31 दिसम्बर तक 35 हजार मेगावाट का आंकड़ा पार कर शीर्ष स्थान हासिल किया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संगठनात्मक कार्यशाला का उद्देश्य राजनीति करना नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को मूल्यों, आदर्शों और जनसेवा के भाव से जोड़ना है। भाजपा की राजनीति सेवा भाव पर आधारित है। हम सब राजनीति में सेवक के रूप में आए हैं और जनसेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करना हमारा लक्ष्य है।

मजनू का टीला के कैफे खतरे में

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 जनवरी। आईएसबीटी के पास स्थित दिल्ली का मजनूं का टीला, अपने सस्ते तिब्बती और एशियाई खाने वाले कैफे के लिए कॉलेज छात्रों में बहुत लोकप्रिय है, परंतु अब यहाँ के कई फूड कोर्ट व कैफे बंद हो सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करें, जो मंज़ूरशुदा बिल्डिंग प्लान और पर्याप्त सुरक्षा इंतज़ामों के बिना चल रहे हैं।

■ **दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, स्वीकृत बिल्डिंग प्लान व पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना जो कैफे चल रहे हैं, उन्हें बंद कर दिया जाए।**

बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि वे इलाके के कई कैफे, बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ उचित कार्रवाई करें, जो सही फायर सेफ्टी व्यवस्था के बिना अवैध रूप से काम कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने उस याचिका का निपटारा किया, जिसमें कहा गया था कि यमुना नदी के किनारे स्थित मजनूं का टीला में कई अनाधिकृत रेस्टोरेंट बहुमंज़िला इमारतों में बिना ज़रूरी कानूनी मंज़ूरी के चल रहे हैं। अदालत ने यह भी नोट किया कि इस मामले में डीडीए पहले ही स्वत: संज्ञान लेकर शिकायत दर्ज कर चुका है।

पूर्वोत्तर छात्रों की सुरक्षा के लिए गठित बेजबरुआ कमेटी की सिफारिशें फिर चर्चा में

देहरादून में एमबीए छात्र एंजल चकमा के नस्लीय उत्पीड़न के बाद हत्या करने से इस समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग की जा रही है

नयी दिल्ली, 03 जनवरी। देहरादून में त्रिपुरा के एमबीए छात्र एंजल चकमा की हाल ही में कथित नस्लीय हमले में हुई हत्या के बाद, एक समिति की 10 साल पुरानी रिपोर्ट और उसकी सिफारिशें फिर से चर्चा में है, जिन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है।

■ **इस समिति का गठन 2014 से किया गया था जब दिल्ली में पूर्वोत्तर भारत के एक छात्र की हत्या कर दी गई थी।**

2014 में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुख्यात नीडो तानियम हत्याकांड के बाद गृह मंत्रालय ने पूर्व आईएएस अधिकारी एमपी बेजबरूआ की अध्यक्षता में बेजबरूआ समिति गठित की थी। इसका उद्देश्य था कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को महानगरों और अन्य शहरों में जिन चिंताओं, भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है, उसकी जांच की जाए और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के उपाय सुझाये जाएं।

बेजबरूआ समिति ने हालांकि नीति स्तर पर उठाये जाने वाले निवारक और दंडात्मक कदमों के साथ विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी और गृह मंत्रालय ने समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए निगरानी समिति बनायी है, लेकिन अब तक कार्रवाई अपर्याप्त रही है।

बेजबरूआ ने कहा, "हमने विभिन्न शहरों में बड़े पैमाने पर लोगों से बात करने के बाद कई सिफारिशें दी थीं। ये सिफारिशें निवारक और दंडात्मक दोनों तरह की हैं।"

पूर्वोत्तर क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों से अलग तरह का मानते हुए बेजबरूआ ने कहा कि जो छात्र और लोग शिक्षा, काम आदि के लिए अन्य महानगरों में जाते हैं, उन्हें नस्लीय प्रकृति के अप्रिय अनुभवों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पुलों का निर्माण रिपोर्ट का मुख्य विषय था।

जब सिफारिशों के क्रियान्वयन के बारे में पूछा गया तो बेजबरूआ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ कदम उठाये गये हैं, जैसे एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर (1093), पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए अलग छात्रावास, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में ज्यादा कुछ नहीं किया गया है।

रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों में से एक थी, नस्लीय प्रकृति की घटनाओं से निपटने के लिए कुछ क्षेत्रों के लोगों के लिए आईपीसी और सीआरपीसी में विशेष प्रावधान शामिल करना। लेकिन, उस महत्वपूर्ण सिफारिश को 2024 के इन कानूनों में तीन नये नियमों- बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए में संशोधन के समय भी अनदेखा कर दिया गया है।

आईपीसी 153 (ए) और (बी) में नस्लीय भेदभाव और दुर्व्यवहार के गंभीर मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थे, निगरानी समिति ने कानून को और सख्त बनाने के लिए संशोधन के समय एक नया प्रावधान 153 (सी) जोड़ने का गृह मंत्रालय को प्रस्ताव दिया।

हालांकि, कानून बनाने वालों ने उस सिफारिश को नजरअंदाज कर दिया, यह बात निगरानी समिति के एक सदस्य ने कही।

बेजबरुआ समिति और उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए गठित निगरानी समिति की सदस्य अलाना गोलमेई ने कहा, हमने पूर्वोत्तर के लोगों के लिए किसी अलग कानून की मांग नहीं की थी।उन्होंने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को जब वे अन्य जगहों पर पढ़ाई या काम के लिए जाते हैं, तो समान भेदभाव का सामना करना पड़ता है।"

महात्मा बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया प्र.मंत्री मोदी ने

■ **मोदी ने कहा उन्हें खुशी है कि उनके नए साल के पहले कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा बुद्ध के कार्यक्रम से हो रही है।**

नयी दिल्ली, 03 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि महात्मा बुद्ध से जुड़े जो भी स्थल हैं, उनका संरक्षण और विकास करना सरकार की प्राथमिकता है। वे महात्मा बुद्ध से संबंधित अवशेषों की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के यहां आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मोदी ने कहा कि सवा सौ साल के इंतजार के बाद महात्मा बुद्ध से जुड़ी भारतीय धरोहर और विरासत वापस लौटी है और अब भारतीय जनमानस इन पवित्र अवशेषों का दर्शन करके उनका आशीर्वाद पा सकेगा। उन्होंने कहा कि 2026 की शुरुआत में ही यह उनके लिए बहुत प्रेरणादायक अवसर है कि उनके पहले सार्वजनिक कार्यक्रम की शुरूआत भगवान बुद्ध के चरणों से हो रही है।

प्रधानमंत्री जिस प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे थे, उन पवित्र अवशेषों में कुछ हड्डियां भी हैं और माना जाता है कि ये भगवान बुद्ध की हड्डियों के अवशेष हैं। ये अवशेष ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के एवं प्राचीनतम माने जाते हैं। इस भव्य प्रदर्शनी में 127 साल बाद पवित्र पिपरहवा की वापस लाई गई वस्तुएं रखी गई हैं। प्रदर्शनी का नाम "प्रकाश और कमल : जागृत व्यक्ति के अवशेष" रखा गया है।

मोदी ने समारोह में कहा कि करोड़ों लोगों ने इन पवित्र अवशेषों का दर्शन किए हैं और ये अवशेष पूरी दुनिया को नयी राह दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत केवल इन अवशेषों का संरक्षक नहीं है बल्कि उनके संदेशों का जीवंत प्रवाह भी है। उन्होंने कहा कि भारत का प्रयास रहता है कि दुनिया में जो स्थल भगवान बुद्ध से जुड़े हैं उनके विकास में भारत सहयोग करे।

बांग्लादेश के क्रिकेटर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बनाकर अभियान चला रही है। वह सड़क किनारे छोटी-छोटी सभाएँ कर रही है और तृणमूल कांग्रेस सरकार की नाकामी और वोट पाने के लिए मुसलमानों को खुश करने की उसकी नीति को उजागर कर रही है। इसी दौरान, बंगाल के इस हिस्से में भी मुस्लिम समुदाय की माँगें बढ़ती जा रही हैं और यहाँ भी अत्याचार की घटनाएँ सामने आ रही हैं। इस क्षेत्र में लगातार साम्प्रदायिक झड़पें हो रही हैं और कुछ मामलों में हिंदुओं पर हमले हुए हैं। राज्य के मुर्शिदाबाद ज़िले में दिनदहाड़े एक पिता-पुत्र की हत्या कर दी गई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में आरोपियों को न तो गिरफ़्तार किया गया और न ही उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। कई अन्य मामलों में राज्य पुलिस ने मुसलमान आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने से भी इनकार किया है। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे इन लगातार अत्याचारों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। ममता ने हिंदुओं की इन भयानक हत्याओं का मुद्दा भी नहीं उठाया है। राज्य भाजपा इन सभी मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है और ममता सरकार पर इन जघन्य घटनाओं पर चुप रहने का आरोप लगा रही है। माना जा रहा है कि लोग इन घटनाओं पर चुपचाप ध्यान दे रहे हैं और आने वाले चुनावों में इसका असर दिखाई दे सकता है।

जब गडकरी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुके हैं। इसके बाद नितिन गडकरी ने अपनी शादी की तारीख भी सही-सही याद कर ली। बातचीत में दिलीप ने गडकरी से अपने गाँव में "एक छोटी सी सड़क" बनवाने की गुज़ारिश की। फराह ने मज़ाक करते हुए कहा कि सड़क को सीधे दिलीप के घर के बीच से ही निकाल सकते हैं। इस पर कंचन गडकरी ने बताया कि उनके अपने पिता के साथ ऐसा हो चुका है, जब सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए उनका घर ही तोड़ दिया गया था।

तृणमूल सांसद मौसम नूर कांग्रेस में शामिल

■ **मौसम नूर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिवंगत एबीए गनी खान चौधरी की भतीजी हैं।**

नयी दिल्ली, 03 जनवरी। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद मौसम नूर शनिवार को फिर कांग्रेस में शामिल हो गयीं, जिसे पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव से पहले वहां सत्तारूढ़ दल को झटका माना जा रहा है। मौसम नूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिवंगत ए.बी.ए. गनी खान चौधरी की भतीजी हैं।

श्रीमती नूर ने राजधानी में कांग्रेस के मुख्यालय पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थित में कांग्रेस की सदस्यता ली। उन्होंने राज्य सभा से इस्तीफा देने की भी घोषणा की है। मालदा लोक सभा सीट से 16वीं और 17वीं लोकसभा में कांग्रेस के टिकट पर जीतीं मौसम नूर 2019 में तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ गयी थीं। उन्हें तृणमूल कांग्रेस ने अप्रैल 2020 में राज्य सभा में भेजा था। उनका राज्य सभा का कार्यकाल आगमी अप्रैल में समाप्त हो रहा था। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष भेज दिया है। नूर ने कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश, पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार तथा लोकसभा सांसद ईशा खान चौधरी की मौजूदगी में पुन: कांग्रेस की सदस्यता ली। इस मौके पर उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने और उनके परिवार के लोगों ने पुन: कांग्रेस के साथ जुड़ कर दिवंगत ए.बी.ए. गनी खान चौधरी (पूर्व केंद्रीय मंत्री) की विरासत को मजबूत करने का निर्णय लिया है।

मनरेगा पर कांग्रेस देश भर में आंदोलन करेगी

■ **कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी 45 दिन का कार्यक्रम करेगी, जिसकी शुरुआत 8 जनवरी से होगी।**

नयी दिल्ली, 03 जनवरी। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) के पक्ष में देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेगी। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में मनरेगा बचाओ अभियान की रूपरेखा तैयार की गई थी।

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 8 जनवरी से सभी प्रदेशों में, बड़ी बैठक की जाएगी, जिसमें प्रदेश के सारे बड़े नेता और प्रभारी मौजूद होंगे। इस बैठक में सभी जिलों के काम का दायित्व दिया जाएगा, 10 जनवरी को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जायेंगी। इसमें पंचायती राज को खत्म करने की साजिश को उजागर किया जाएगा।

11 जनवरी को सभी जिलों में , महात्मा गांधी जी या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने एक दिन का उपवास किया जाएगा। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक हर पंचायत में चौपाल लगाई जायेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से सभी ग्राम प्रधानों को पत्र लिखा जाएगा।

30 जनवरी को वार्ड और ब्लॉक लेवल पर कार्यक्रम किया जाएगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के बाहर धारण दिया जाएगा। 7 फरवरी से 15 के बीच विधानसभा और राज्यभवन का घेराव कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें सभी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। 16 फरवरी से 25 फरवरी के बीच कांग्रेस पार्टी बड़ी रैली करेगी।

दिल्ली में 72 उड़ानें रद्द हुईं

नयी दिल्ली, 03 जनवरी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को खराब मौसम के कारण 72 उड़ानें रद्द रहीं और 300 से अधिक उड़ानों की आवाजाही में देरी हुई।

दिल्ली में आज सुबह कोहरा नहीं था, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में कोहरे के कारण वहां से आने वाली और वहां जाने वाली उड़ानें रद्द रहीं।

हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न विमान सेवा कंपनियों ने आज दिल्ली आने वाली 34 और यहां से जाने वाली 38 उड़ानें रद्द कीं।

इसके अलावा 300 से अधिक उड़ानों में देरी की भी सूचना है।

उल्लेखनीय है कि आज दिल्ली में रनवे पर दृश्यता ठीक रही, लेकिन दूसरे शहरों में कोहरा रहा।

अमेरिका ने वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शहर के कुछ हिस्सों से काले धुएं के गुबार उठते देखे। धमाके और विमानों को लगभग 90 मिनट तक देखा गया।

एसोसिएटेड प्रैस द्वारा सत्यापित वीडियो में कैराकस और एक अनजान तटीय शहर के ऊपर रात में आकाश में धुएं के गुबार साथ बार-बार मूक धमाके देखे गए, जो आसपास की पहाड़ियों को रोशन कर रहे थे। अन्य फुटेज में कारें राजमार्गों पर चलती हुई दिखाई दीं, जबकि उनके पीछे तेज धमाकों की रोशनी दिख रही थी।

फैडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र और नज़दीकी क्यूरासाओ में अमेरिकी वाणिज्यिक और निजी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया, यह कहते हुए कि "चल रही सैन्य गतिविधियों से जुड़ी उड़ानें सुरक्षा जोखिम" हैं।

ट्रंप की घोषणा के बावजूद, वाइट हाउस या पेंटागन से तुरंत कोई विस्तृत ब्रीफिंग नहीं आई। पेंटागन ने प्रश्नों का जवाब वाइट हाउस को दिया, जबकि अमेरिकी दक्षिणी कमांड ने प्रतिक्रिया नहीं दी। ट्रंप फ्लोरिडा के अपने निजी क्लब में थे और सोशल मीडिया पर अपनी प्रारंभिक पोस्ट के बाद उन्होंने कोई और टिप्पणी नहीं दी।

रॉयटर्स ने बाद में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर हमले किए, हालांकि लक्ष्यों या उद्देश्यों के बारे में विवरण नहीं दिया गया।

ट्रंप प्रशासन मादुरो पर 5 माह से दबाव बढ़ा रहा था, मादुरो पर अमेरिका ने नार्को आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। अगस्त से, वॉशिंगटन ने वेनेजुएला के उत्तरी तट के पास एक बड़े बेस के निर्माण का आदेश दिया, जिसमें एक विमान वाहक पोत, युद्धपोत और उन्नत लड़ाकू जेट्स शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य उपस्थिति है।

सितंबर की शुरुआत से, अमेरिकी सैन्य बल कैरेबियाई सागर और पूर्वी प्रशांत में नौकाओं पर हमले कर रहा है, उसका आरोप था कि इनमें नशीले पदार्थ हैं।

अमेरिका ने डेटा जारी कर 35 नावों पर हमलों और कम से कम 115 लोगों की मौत की सूचना दी थी। ट्रंप ने इन अभियानों को यूएस में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए आवश्यक बताया और कहा कि वॉशिंगटन ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ "सशस्त्र संघर्ष" में जुटा है।

पिछले सप्ताह, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के एक ऐसे क्षेत्र पर हमला किया था, जहां नौकाओं में नशीले पदार्थ लदे हुए थे। वर्तमान दबाव अभियान के दौरान वेनेजुएला की ज़मीन पर की गई यह पहली स्थल सैन्य कार्यवाही थी। अन्य मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है कि इन ऑपरेशन्स के पीछे सीआईए थी।

सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ, वॉशिंगटन ने प्रतिबंधों का भी विस्तार किया है। प्रतिबंधित तेल टैंकरों को ज़ब्त किया है और कहा कि ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल पर जो रोक लगाई है, वह काराकस पर आर्थिक दबाव को कड़ा करने के उद्देश्य से उठाए गए कदम हैं। रॉयटर्स के अनुसार, ट्रंप ने बार-बार ज़मीन पर हमलों की धमकी दी है और निजी तौर पर मादुरो से देश छोड़ने का आग्रह किया है। इस सप्ताह के शुरू में, उन्होंने कहा कि मादुरो के लिए यह "समझदारी" होगी कि वे सत्ता से हट जाएं।

वेनेजुएला ने अमेरिकी "सैन्य आक्रमण" को नकारते हुए, वॉशिंगटन पर देश के तेल और खनिज संसाधनों को हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सरकार ने कहा कि अमेरिका "सफल नहीं होगा" इन संसाधनों को लेने में, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की निंदा करने की अपील की।

एक बयान में, सरकार ने कहा कि मादुरो ने "सभी राष्ट्रीय रक्षा योजनाओं को लागू करने का आदेश दिया है" और "बाहरी संकट की स्थिति" घोषित की है, जिससे अधिकारियों को विस्तारित आपातकालीन शक्तियाँ और सशस्त्र बलों को एक बड़ी भूमिका मिलेगी।

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्टावो पेट्रो ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैराकस पर बमबारी की जा रही है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकाल बैठक का आ ान किया। बाद में उन्होंने वह सूची प्रकाशित की, जिसमें बमबारी की गई साइटों का उल्लेख किया गया है, इनमें कैराकस में क्युएर्टेल डे ला मोंटाना बैरक भी शामिल था, जो ह्यूगो चावेज़ का मकबरा है, जो चैविज़्मो के राजनीतिक आंदोलन का केन्द्रीय प्रतीक है, यह आंदोलन 1999 से वेनेजुएला पर शासन कर रहा है।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमलों की निंदा की, और ईरानी राज्य टेलीविजन ने कैराकस में धमाकों के दृश्य प्रसारित किए। क्यूबा, जो मादुरो का करीबी सहयोगी और अमेरिका का दीर्घकालिक विरोधी है, ने भी हमले की निंदा की।

जैसे-जैसे स्थिति स्पष्ट होती है, शनिवार की सुबह की घटनाएँ न सिर्फ वेनेजुएला की आंतरिक राजनीति को फिर से आकार देने की संभावना रखती हैं, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता और लैटिन अमेरिका में अमेरिकी संबंधों को भी प्रभावित कर सकती हैं।

टूंप ने एक फोटो भी जारी किया, जिसमें मादुरो की आंखों पर पट्टी बंधी हुई दिख रही थी।

'देशभर में फॉरेंसिक लैब का जाल बिछाया जाएगा'

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि इस पर 30 हजार करोड़ रु. की लागत आएगी

■ **सरकार का विज़न है कि अपराधिक मामलों में त्वरित न्याय मिले।**

नयी दिल्ली, 03 जनवरी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले पांच वर्षों में देशभर में फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं का जाल बिछाया जायेगा, जिसपर 30 हजार करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 तक देश के हर राज्य में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय या केन्द्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला बनायी जायेगी।

शाह ने शनिवार को अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के विजयपुरम में मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का विषय सेंट्रल फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला था। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बंडी संजय कुमार, संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य, गृह सचिव, विश्वविद्यालय के कुलपति और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया।

शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने 2019 से लेकर अब तक संसदीय परामर्शदात्री समिति की 12 बैठकें की हैं, जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का विजन है कि आपराधिक कानूनों के पूरी तरह लागू होने के बाद समय पर न्याय मिले। उन्होंने कहा कि सरकार 2029 तक ऐसी व्यवस्था बनायेगी, जिसमें तीन साल की अवधि में प्राथमिकी से लेकर उच्चतम न्यायालय तक न्याय की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो सकेगी। उन्होंने कहा कि 2022 से अब तक हुए सुधार इसी दिशा में किए गए प्रयास हैं। गृह मंत्रालय इन प्रयासों की व्यापक निगरानी कर रहा है और कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि न्याय देने की प्रक्रिया के लिए फॉरेंसिक क्षमताओं में बढ़ोतरी और विस्तार के लिए सरकार ने 2020 से ही फॉरेंसिक्स पर ध्यान केन्द्रीत करके काम किया। उन्होंने कहा कि नई न्याय संहिताएं पिछले वर्ष जुलाई से अमल में हैं परंतु फॉरेंसिक्स की दृष्टि से इसे लागू करने का काम 2020 से ही शुरू कर दिया था, जिसके सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं।

शाह ने कहा कि पहले देश के सामने पांच चुनौतियां थीं, जिनमें फॉरेंसिक जांच में प्रौद्योगिकी की कमी, साक्ष्य की गुणवत्ता का सीमित होना, कई जगहों पर पुलिस द्वारा फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट अदालत में नहीं देना, कुशल पेशेवरों और फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की कमी और राष्ट्रव्यापी मापदंडों की कमी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नए कानून के प्रावधानों के मुताबिक अब फॉरेंसिक प्रयोगशाला अपनी रिपोर्ट सीधी अदालत को भेजेगी और उसकी एक प्रति पुलिस को देगी।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गत नवंबर से देश के हर पुलिस स्टेशन को अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम पर ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे हर प्राथमिकी सेंट्रल सर्वर पर उपलब्ध है। अपराध की मैपिंग के लिए आने वाले दिनों में मोडस ऑपरेन्डी ब्यूरो भी बनाया जाने वाला है। लगभग 36 करोड़ डाटा के साथ 7 लाख प्राथमिकी का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908